an>

Title: Need to take steps to implement various development schemes uniformly in Shrawasti Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें अपनी बात सदन में रखने का अवसर प्रदान किया।

मैं भारत सरकार द्वारा संचालित ग्राम विकास संबंधित समस्त योजनाओं का उत्तर प्रदेश में हो रहे दुरुपयोग एवं भेदभाव की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के श्रावस्ती एवं बलरामपुर जिले भारत सरकार द्वारा चयनित पिछड़े क्षेत्र में सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से विकास कार्यों के लिए विशेष धनराशि जारी की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी विभिन्न मदों में ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास हेतु धन उपलब्ध करवाता है। भारत सरकार द्वारा जारी भारी धनराशि का उपयोग गिने-चुने चंद लोहिया ग्रामों में ही किया जा रहा है जिसके कारण लगभग तीन-चौथाई गाँवों में केन्द्रीय योजनाओं के तहत कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके पूर्व पिछली पंचवर्षीय योजना में भी केन्द्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की धनराशि का केवल अंबेडकर गाँवों में उपयोग किया जा रहा था जिसकी वजह से शेष गाँव बिना विकास के अधूरे पड़े हुए हैं। इंदिरा आवास योजना, पेयजल योजना, प्रधान मंत्री सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सहित सभी योजनाओं के तहत विकास कार्यों में इस तरह के भेदभाव के कारण विकास से अछूते तमाम गाँवों के निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ लोहिया समग्र गांवों में काम हो रहा है। महोदया, पहले केवल चंद अंबेडकर गांवों में और वर्तमान में चंद लोहिया गांवों में विकास कार्यों के लिए भारत सरकार का धन उपयोग कर तीन-चौथाई गाँवों को विकास से अछूता रखना सर्वथा अनुचित है। मेरा न लोहिया गांवों से विरोध है और न अंबेडकर गंवों से विरोध है। लेकिन शेष गांवों के विकास की भी चिन्ता हम सबको करनी चाहिए, यही मांग हम सदन के माध्यम से करते हैं।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दहन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।